सच्ची मुच्ची

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय की पत्रिका

दिसम्बर 2011

प्रगतिशील व धर्मनिरपेक्ष लोगों को चाहिए कि वे अण्णा आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लें ताकि संघ परिवार चाह कर भी इस आंदोलन का चुनावी फायदा न उठा पाए

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव फरवरी 2012 में होना तय हुआ है। सच्ची मुच्ची जनवरी 2012 अंक आम लोगों के जीवन से जुड़े मुद्दों पर ही आधारित होगा।

आपका वोट जिस उम्मीदवार को जाएगा उसका चुनाव घोषणा–पत्र में क्या मुद्दे होने चाहियें?

– आप अपने विचार पृष्ठ 3 पर दिए हुए सच्ची मुच्ची व्यवस्थापकीय सम्पर्क पर भेजें–

जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, आशा परिवार एवं लोक राजनीति मंच की अपील है कि आप किसी भी भ्रष्ट उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी का समर्थन न करें। कृपया अपना वोट ईमानदार उम्मीदवार को ही दें भले ही वो निर्दलीय हो या उसकी/ उसके जीतने की सम्भावना कम हो।

विषय सूची

1. अण्णा हजारे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ...3
2. कार्यस्थल पर शिशु–सदन अनिवार्य............7
3. शांति एवं लोकतंत्र पाक–भारत लोकमंच....10
4. खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूँजी निवेश.......12
5. योजना आयोग और छोटे–सीमान्त किसानः14
6. वर्तमान व्यवस्था का विकल्प.........................17
7. विश्व बैंक, सोमालिया और अकाल..............19

सच्ची मुच्ची
वर्ष 10: अंक 12 दिसम्बर 2011

सम्पादक मण्डल
एस.आर.दारापुरी 9415164845
नागेश त्रिपाठी 9452112004
अरविन्द मूर्ति 9839835032
रोमा 9415233583
राजीव यादव 9452800752
शाहनवाज़ आलम 9415254919
ईमेलः ashaashram@yahoo.com
फैक्सः 0522–2358230

सलाहकार मण्डल
मेधा पाटकर, अरूणा राय, कविता श्रीवास्तव, योगेन्द्र यादव, अजीत झा, रवि किरण जैन, नीलाभ मिश्र, अजीत साही, जे.पी. सिंह, डॉ. सुनीलम्

व्यवस्थापकीय सम्पर्कः
डॉ. संदीप पाण्डेय
ए–893, इन्दिरा नगर, लखनऊ–226016.उ0प्र0
फोनः 0522–2347365, 9839073355
ईमेलः ashaashram@yahoo.com

विज्ञापन: देवेश पटेल 9919841007
वितरण: वल्लभाचार्य, प्रदीप सिंह
'लेआउट, डिज़ाइन, प्रकाशन':
सी.एन.एस. www.citizen-news.org

सहयोग राशिः रूपये 10 मात्र
वार्षिक सहयोग राशिः रूपये 100 मात्र
वार्षिक सहयोग राशि मनीआर्डर द्वारा व्यवस्थापकीय पते पर भेजें।

अण्णा हजारे के आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल है

अण्णा हजारे के आंदोलन के बारे में शुरू से यह कहा जा रहा है कि इसके पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या हिन्दुत्ववादी शक्तियां हैं जो चाहती हैं कि इस आंदोलन का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिले। आंदोलन की तरफ से कई बार यह स्पष्टीकरण भी आ चुका है कि अण्णा हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ शामिल नहीं हैं। फिर भी भारतीय जनता पार्टी व संघ परिवार के इस आंदोलन के प्रति नरम रवैये से यह संदेह बना रहा।

21 दिसम्बर, 2011, को अमेठी, उ.प्र., में मेधा पाटकर के आगमन पर इस आंदोलन की एक बैठक का आयोजन हुआ जिसमें मैं भी भाग ले रहा था। असल में मेधा पाटकर का यह दौरा जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय द्वारा आयोजित किया गया था। बैठक में एक वक्ता दिग्विजय सिंह की इस बात के लिए आलोचना कर रहा था कि वे बार–बार ये आरोप लगाते हैं कि इस आंदोलन के पीछे संघ परिवार है। तभी संघ परिवार से जुड़े एक व्यक्ति ने हस्तक्षेप करते हुए यह कहा कि संदीप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देशद्रोही बताते हैं। ऐसा मेरे एक लेख में लिखा था जो वहां वितरित की जा रही जन आंदोलनों के राष्ट्रीय समन्वय की हिन्दी पत्रिका 'सच्ची–मुच्ची' के सितम्बर अंक में प्रकाशित हुआ था।

> भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का अवैध लेन–देन ही नहीं है। साथी इंसान को बराबरी का दर्जा न देना या किसी भी आधार पर इंसानों के साथ भेदभाव करना भी भ्रष्टाचार है। हिंसा का प्रयोग भी भ्रष्टाचार है।

जब मेरे बोलने की बारी आई तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों का अवैध लेन–देन ही नहीं है। साथी इंसान को बराबरी का दर्जा न देना या किसी भी आधार पर इंसानों के साथ भेदभाव करना भी भ्रष्टाचार है। हिंसा का प्रयोग भी भ्रष्टाचार है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसने इस देश में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, ने हिंसा का इस्तेमाल कई बार किया है। संघ परिवार से जुड़े लोगों पर देश में हुए कम से कम पांच बम विस्फोटों में हाथ होने की बात जांच के बाद सामने आई है। इनमें से दो घटनाएं मालेगांव की हैं और शेष हैदराबाद, अजमेर व समझौता एक्सप्रेस की। वह संगठन जो अपने ही देश में बम विस्फोट कराता हो राष्ट्रभक्त तो कहला नहीं सकता, वह तो देशद्रोही ही हो सकता है। मेरी बात सुनते ही वहां उपस्थित सात–आठ संघ परिवार के कार्यकर्ता आक्रामक मुद्रा में आ गए। उनका कहना था कि मुझे अपने कथन के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। बल्कि धमकी दी जाने लगी कि माफी मांगे बिना मुझे जाने न दिया जाएगा। यह भी कहा गया कि जिस तरह प्रशांत भूषण की पिटाई की गई उसी तरह मेरी भी पिटाई होगी। वहां अफरा तफरी मच गई। आयोजक ने सुझाव दिया कि मैं वहां से हट जाऊं। मुझे वहां से बच कर निकलना कायरता समझी। मैंने आयोजक से कहा कि मैं कुछ भी झेलने के लिए तैयार हूं।

फिर माफी मांगने के लिए मेरे ऊपर दबाव पड़ने लगा। उनमें से कुछ लोग कहने लगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में अच्छे लोग भी हैं। मैंने आखिर में फिर स्पष्टीकरण दिया। मैंने कहा कि संघ परिवार के लोग जो अच्छा काम करते हैं उसके लिए तो उनकी तारीफ की जा सकती है। जैसे आपदा के समय राहत कार्य करने में संघ परिवार के लोग सबसे पहले पहुंचने वालों में से होते हैं। लेकिन मैंने कहा कि चाहे मुझे जूते से मारें या जान से, सच्चाई कहने से मैं नहीं डरुंगा। उदाहरण के लिए गांधी की हत्या के आरोप से संघ परिवार कभी मुक्त नहीं हो सकता। संघ परिवार के लोग मुझे पीटना चाहते थे लेकिन मेरे साथियों व पुलिस ने कार्यक्रम सम्पन्न होने पर मुझे सुरक्षित वहां से निकाल दिया।

इस घटना से एक बात साफ हो गई कि अण्णा हजारे के आंदोलन में संघ परिवार की घुसपैठ है। किसी रसायनिक प्रक्रिया की तरह एक प्रयोग का तुरंत परिणाम दिखाई पड़ा। बल्कि मेरा विरोध करने वालों में से एक ने कहा कि अण्णा आंदोलन में प्रमुख लोगों के तो सिर्फ चेहरे हैं। भीड़ तो संघ परिवार के लोग ही जुटा रहे हैं।

वैसे असलियत यह नहीं है। अण्णा के आंदोलन में संघ के लोग जरूर होंगे लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं है। वे दस–बीस प्रतिशत ही हैं। ज्यादातर लोग स्वयं स्फूर्त तरीके से शामिल हुए हैं। कम से कम आंदोलन का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है उनमें से अरविंद केजरीवाल व प्रशांत भूषण के बारे में तो साफ कहा जा सकता है कि वे साम्प्रदायिक नहीं हैं। इसलिए यह बात तो निराधार है कि अण्णा हजारे के आंदोलन के पीछे संघ परिवार है।

किन्तु संघ परिवार इसमें है जरूर। यह समझा भी जा सकता है। जबकि भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कमजोर पड़ चुकी है और महंगाई, आदि, मुद्दों पर कोई प्रभावशाली भूमिका ले पाने में नाकाम रही है, अण्णा का आंदोलन उसके लिए एक वरदान है। इस समय मुख्य विपक्ष की भूमिका में भाजपा की जगह अण्णा का आंदोलन आ गया है। अण्णा का आंदोलन गैर राजनीतिक है इसलिए इस आंदोलन का सारा चुनावी लाभ तो भाजपा को ही मिलेगा। यानी बिना मेहनत भाजपा को फायदा हो रहा है।

अण्णा के आंदोलन में संघ के लोग जरूर होंगे लेकिन उनकी तादाद ज्यादा नहीं है। वे दस–बीस प्रतिशत ही हैं। ज्यादातर लोग स्वयं स्फूर्त तरीके से शामिल हुए हैं। कम से कम आंदोलन का नेतृत्व जिन लोगों के हाथ में है उनमें से अरविंद केजरीवाल व प्रशांत भूषण के बारे में तो साफ कहा जा सकता है कि वे साम्प्रदायिक नहीं हैं। इसलिए यह बात तो निराधार है कि अण्णा हजारे के आंदोलन के पीछे संघ परिवार है।

अण्णा के आंदोलन में संघ परिवार के शामिल होने का दूसरा सबूत है इसमें लगने वाले नारे। दो नारे जो प्रमुख रूप से लगाए जाते हैं वे हैं 'भारत माता की जय' व 'वंदे मातरम्'। ये दोनों नारे संघ की पहचान हैं। हलांकि कुछ मध्यम वर्गीय लोग इन नारों को आजादी के आंदोलन के महौल को पुनर्जीवित करने के लिए भी लगाते हैं क्योंकि अण्णा ने कहा है कि यह भारत की दूसरी आजादी की लड़ाई है।

20 दिसम्बर को वाराणसी में और 22 दिसम्बर को बिलारी, मुरादाबाद में मेधा पाटकर के आगमन पर जो सभाएं हुई उनमें उपर्युक्त नारे नहीं लगे। इन दोनों सभाओं में गरीब लोग बड़ी संख्या में भागीदारी निभा रहे थे जो अपनी आजीविका या अस्तित्व की लड़ाई लड़

रहे हैं। गरीब लोगों के लिए उपर्युक्त दोनों नारों का कोई विशेष अर्थ नहीं है। उनके संघर्ष के अलग नारे हैं।

जो लोग अण्णा आंदोलन के ऊपर संघ परिवार से रिश्ते का आरोप लगाते हैं वे आंदोलन के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। भ्रष्टाचार सभी का मुद्दा है।

सभी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो। प्रगतिशाील व धर्मनिरपेक्ष लोगों को चाहिए कि वे अण्णा आंदोलन में बढ़–चढ़ कर हिस्सा लें ताकि संघ परिवार चाह कर भी इस आंदोलन का चुनावी फायदा न उठा पाए।

– डॉ0 संदीप पाण्डेय

भारतीय जनता पार्टी खुद भ्रष्टाचार के आरोपों के चलते कमजोर पड़ चुकी है और महंगाई, आदि, मुद्दों पर कोई प्रभावशाली भूमिका ले पाने में नाकाम रही है, अण्णा का आंदोलन उसके लिए एक वरदान है। इस समय **मुख्य विपक्ष की भूमिका में भाजपा की जगह अण्णा का आंदोलन आ गया है**। अण्णा का आंदोलन गैर राजनीतिक है इसलिए इस आंदोलन का **सारा चुनावी लाभ तो भाजपा को ही मिलेगा।** यानी बिना मेहनत भाजपा को फायदा हो रहा है।

कार्यस्थल पर शिशु–सदन अनिवार्य होना चाहिए
– योजना आयोग का आश्वासन –

घटनाः

यह दिल दहलाने वाली घटना १६ दिसम्बर २०११ को हुई जब भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान, गांधीनगर में कार्यरत मजदूरों ने एक निर्माणाधीन भवन में अपने २ महीने के शिशु आकाश को रख कर खाना बनाना आरंभ किया. १० बजे रात जब मजदूरों ने शिशु को देखा तो पाया कि शिशु गायब है। उसको ढूंढना आरंभ किया गया और पता चला कि पास के कुछ २–३ कुत्ते शिशु को तब–तक अधकचरा खा चुके थे. संभवतः यह कुत्ते ही इस शिशु को उठा ले गए थे.

मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के गाँव से आये और अनुसूचित जनजाति के लक्ष्मण, २२ वर्ष, और रैना, २० वर्ष, का यह बच्चा आकाश २ माह का था. यह अत्याधिक क्रूर घटना इसीलिए हुई क्योंकि मजदूर–श्रमिक वर्ग के लिये सामाजिक सुरक्षा दूभर है. सिर्फ शोक प्रकट करने से कहीं ज्यादा हमें इस समस्या को सुलझाने के लिये कहीं अधिक प्रयास करने होंगे.

वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता **डॉ संदीप पाण्डेय,** जो गांधीनगर, गुजरात, स्थित भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान में अतिथि–आचार्य हैं, ने यह मांग कीः

१) भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान के परिसर पर तुरंत ६ वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिये शिशुसदन आरंभ हो. भारतीय प्रद्योगिकी संस्थान पहले से ही इस सुझाव पर विचाराधीन है और अब उसको एक जगह और एक संचालक की व्यवस्था करनी चाहिए. बच्चों को पौष्टिक आहार भी एक मर्तबा मिलना चाहिए और इसका खर्चा भवन निर्माण के ठेकेदार को वहन करना चाहिए.

२) इन मजदूरों के लिये ठेकेदार द्वारा एक कमरे के आवास, जैसे कि सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रदान किया जाते हैं, बनाये जाएँ जो सुरक्षित हो (दरवाजा और खिड़की आदि सही से लगी हो) और शौच आदि की व्यवस्था भी हो जिसका सभी मजदूर और उनके परिवार के सदस्य गरिमा के साथ इस्तेमाल कर सकें.

अहमदाबाद, गुजरात, में एक मजदूर के २ महीने के शिशु आकाश को कुत्तों ने खा लिया. यह निः संदेह ही अत्यंत जघन्य घटना है और समाज में व्याप्त असमानताओं का मापक है.

डॉ संदीप पाण्डेय ने जब योजना आयोग को रपट की तो योजना आयोग की वरिष्ठ सदस्या और स्वास्थ्य समिति की अध्यक्षा डॉ सईदा हमीद ने ईमेल पर आश्वासन दिया कि १२वीं पंच वर्षीया योजना में कार्यस्थल पर शिशु–सदन या पालना–घर अनिवार्य होंगे और ऐसा सुझाव वो अपनी सहकर्मियों को भेज रही हैं जो इस दिशा में ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय को निर्देशित करेंगे.

असंवेदना की हद तब हुई जब कुछ स्थानीय लोगों ने इसे 'कुत्ता पकड़ने' का मुद्दा समझा. यह कुत्ते–भेड़िये का मुद्दा नहीं है, वरन **जिन हालातों में मजदूर वर्ग जी रहा है उस पर सवाल उठाता है**. किसी भी भवन निर्माण से पहले जैसे जमीन पंजीकृत करवाना, नक्शा पारित करवाना, जरूरी संस्तुति लेना (जैसे कि पर्यावरण आदि) अनिवार्य है, वैसे ही यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि मजदूरों के रहने के लिये मानवीय रूप से स्वीकार्य और सुरक्षित इंतजाम हो.

जब कार्यस्थल पर पालना घर और शिशु सदन होंगे तो बच्चों को पर्याप्त आहार मिल सकेगा और अपने माता–पिता या अभिभावकों का निरीक्षण और स्नेह भी.

विशेषज्ञों, विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार, नवजात शिशु के लिये जन्म–उपरांत ६ महीने तक माँ का दूध सर्वोत्तम आहार है. परन्तु जब कार्यस्थल पर पालना घर और शिशुसदन नहीं होंगे और गर्भवती स्त्री को बिना–वेतन काटे प्रसूति उपरांत ६ महीने तक अवकाश नहीं मिलेगा तो यह कैसे संभव होगा कि शिशु पर्याप्त स्तनपान कर सके? जन्म से ६ माह बाद भी १८ माह तक कम–से–कम स्तनपान और अन्य भोजन शिशु के लिये आवश्यक

किसी भी भवन निर्माण से पहले जैसे जमीन पंजीकृत करवाना, नक्शा पारित करवाना, जरूरी संस्तुति लेना (जैसे कि पर्यावरण आदि) अनिवार्य है, वैसे ही यह भी अनिवार्य होना चाहिए कि मजदूरों के रहने के लिये मानवीय रूप से स्वीकार्य और सुरक्षित इंतजाम हो.

है. इसीलिए कार्यस्थल पर पालना घर और शिशुसदन होना अनिवार्य होना चाहिए.

केवल स्तन–पान ही बच्चों को अनेक प्रकार के रोगों, विशेषकर निमोनिया, से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। माँ का दूध ही शिशु को अनेक पोषक तत्व देता है साथ ही इम्यूनोग्लोबिन, प्रतिरोधक तत्व भी प्रदान करता है।

इन तत्वों से शिशुओं को 'वसननली' संबंधित रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है।

तथा इनके द्वारा बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। स्तन–पान न करने वाले बच्चे स्तन–पान करने वाले बच्चों की अपेक्षा पाँच गुना अधिक संख्या में निमोनिया रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त करते हैं.

देखना यह है कि योजना आयोग का आश्वासन कि सभी कार्यस्थलों पर शिशु–सदन और पालना घर अनिवार्य हों, क्या 12वीं पंच वर्षीय योजना में लागू होता है या नहीं।

– **शोभा शुक्ला**, सी.एन.एस.

शांति एवं लोकतंत्र के लिए पाकिस्तान–भारत लोकमंच का आठवॅा संयुक्त अधिवेशन इलाहाबाद में सम्पन्न

शांति एवं लोकतंत्र के लिये पाकिस्तान–भारत लोकमंच का आठवें संयुक्त अधिवेशन इलाहाबाद में २६–३१ दिसम्बर २०११ के दौरान आयोजित होना तय हुआ है जिसमें दोनों देशों से अनेक वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एवं शांति और लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले नागरिक भाग लेंगे. इस अधिवेशन के माध्यम से यह सन्देश जायेगा कि दक्षिण एशिया के नागरिकों को और सरकारों को यह कदम उठाने चाहिए:

१. दक्षिण एशिया के देशों के बीच दोस्ती और सहयोग में सुधार हो और मेल बढ़े. इसके लिये इन देशों को वीसा–मुक्त होना चाहिए जिससे कि इस छेत्र के लोग पूरी स्वतंत्रता के साथ एक दुसरे से मिल सकें, और इस छेत्र की मिलीजुली सांस्कृतिक धरोहर की जड़ें मजबूत हों, और व्यापर बढ़े.

२. इन देशों में लोकतान्त्रिक एवं मानवीय मूल्यों को सशक्त किया जाए और समाज के हाशिये पर रह रहे वर्गों के लिये सामाजिक एवं कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाए, जिनमें महिलाएं, दलित, और अन्य धार्मिक और प्रजातीय अल्प–संख्यक वर्ग शामिल हैं. हमारा मानना है कि सक्रियता से इन वर्गों का शोषण करने वाले कानूनों और सामाजिक प्रथाओं को खत्म किया जाये.

३. भारत और पाकिस्तान को एक निश्चित समयकाल में अपने परमाणु अस्त्र–शास्त्र को खत्म करना आरंभ

भारत और पाकिस्तान को एक निश्चित समयकाल में अपने परमाणु अस्त्र–शास्त्र को खत्म करना आरंभ करना चाहिए जिससे कि दोनों देश मिल कर परमाणु मुक्त दक्षिण एशिया छेत्र स्थापित करने में पहल ले सकें

करना चाहिए जिससे कि दोनों देश मिल कर परमाणु मुक्त दक्षिण एशिया छेत्र स्थापित करने में पहल ले सकें.

४. जापान में घटित परमाणु आपदा के बाद तो यह और भी स्पष्ट हो गया है कि परमाणु शक्ति का सैन्य या ऊर्जा दोनों में ही इस्तेमाल नहीं होना चाहिए.

५. लोकतान्त्रिक मूल्य और शासन प्रणाली सम्पूर्ण दक्षिण एशिया छेत्र में कायम होनी चाहिए.

६. दक्षिण एशिया छेत्र की सभी सरकारों द्वारा बिना–विलम्ब सैन्यकरण को रोकने के लिये कदम उठाये जाने चाहिए और सैन्य बजट को पारदर्शी तरीकों से जन–हितैषी कार्यक्रमों में निवेश करना चाहिए जैसे कि शिक्षा एवं स्वास्थ्य.

७. चूँकि इस छेत्र की सांस्कृतिक धरोहर मिलीजुली है, सक्रियता के साथ हमें शांति और आपसी सौहार्द बढ़ाने के लिये सांप्रदायिक ताकतों पर अंकुश लगाना चाहिए.

८. हमारा मानना है कि इस छेत्र के सभी सरकारों को कदम उठाने चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल और जमीन, पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार कायम रहे, और गैर–कानूनी और विध्वंसकारी तरीकों से जल,जंगल और जमीन को वैश्वीकरण ताकतों से बचाना चाहिए क्योंकि यह जन–हितैषी नहीं है.

— इरफान अहमद
उपाध्यक्ष, शांति एवं लोकतंत्र के लिये
पाक–भारत लोकमंच (उ0प्र0)

इस छेत्र के सभी सरकारों को कदम उठाने चाहिए कि प्राकृतिक संसाधन जैसे कि जल, जंगल और जमीन, पर स्थानीय लोगों का ही अधिकार कायम रहे, और गैर–कानूनी और विध्वंसकारी तरीकों से जल,जंगल और जमीन को वैश्वीकरण ताकतों से बचाना चाहिए क्योंकि यह जन–हितैषी नहीं है.

खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूँजी निवेश से गरीबी, शोषण बढ़ेगा

सस्ते सामान की चुकानी पड़ेगी बड़ी महंगी कीमत

खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश स्थानीय लोगों एवं देश की अर्थ व्यवस्था के लिये कितना खतरनाक हो सकता है यही दर्शाया गया है वृत्त–चित्र *'वाल–मार्ट: हाई कास्ट ऑफ लो प्राइस'* में. इस वृत्त–चित्र को आशा परिवार, जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय, जहांगीराबाद मीडिया इंस्टिट्यूट, नागरिकों का स्वस्थ लखनऊ अभियान, एवं सी.एन.एस. द्वारा लखनऊ में प्रदर्शित किया गया था।

मग्सेसे पुरुस्कार से सम्मानित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डॉ संदीप पाण्डेय ने कहा कि खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय हमारे देश की अधिकांश जनता के लिये हितकारी नहीं है. इससे पैसे का धुरुवीकरण होगा, अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होंगे. डॉ संदीप पाण्डेय ने कहा कि भारत को ग्राम स्वराज्य के सपने को असल में साकार करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों के लिये दीर्घकालिक एक मानवीय सामाजिक व्यवस्था बन सके. उदहारण के तौर पर उदारीकरण नीतियों से भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को नुक्सान ही पहुंचा है और अधिकाँश जनता, जो गरीब है, उसका जीना और अधिक दूभर हो गया है. भारत को चाहिए कि खुदरा व्यवसाय पर निर्भर लोगों को और मजदूर–किसान वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो जिससे कि मजदूर या किसान आत्महत्या करने पर न विवश हों और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें.

खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय हमारे देश की अधिकांश जनता के लिये हितकारी नहीं है. इससे पैसे का **धुरुवीकरण** होगा, अमीर और अधिक अमीर और गरीब और अधिक गरीब होंगे.

इस वृत्त–चित्र में प्रदर्शित किया गया है कि वाल–मार्ट ने अमरीका के अनेक प्रदेशों से आर्थिक अनुदान ले कर उन प्रदेशों में अपने स्टोर खोले. वाल–मार्ट के कर्मचारियों को पूरे मुनासिब वेतन न देना, सुबह से ले कर रात देर तक काम लेना पर ओवर–टाइम न देना, जब वे वाल–मार्ट द्वारा दिए गए घरों में नहीं रह रहे हैं फिर भी किराया वेतन से काटना, पर्यावरण प्रदूषित करना, आदि अनेक मुद्दें इस फिल्म में दर्शाए गए हैं. वाल–मार्ट जिन समुदाओं में अपने स्टोर खोलता है

वहां की जमीन की कीमत तक गिर जाती है क्योंकि स्थानीय व्यावसायिक प्रतिष्ठान खाली होते जाते हैं और खाली बिल्डिंगों की कतार लग जाती है. इस फिल्म में यह भी दर्शाया गया है कि वाल–मार्ट स्टोर में अवैध प्रवासियों को साफ–सफाई के लिये रात में स्टोर के भीतर बंद कर दिया गया और सुबह ही स्टोर खुलने पर बाहर निकाला गया.

– **बॉबी रमाकान्त** – सी.एन.एस.

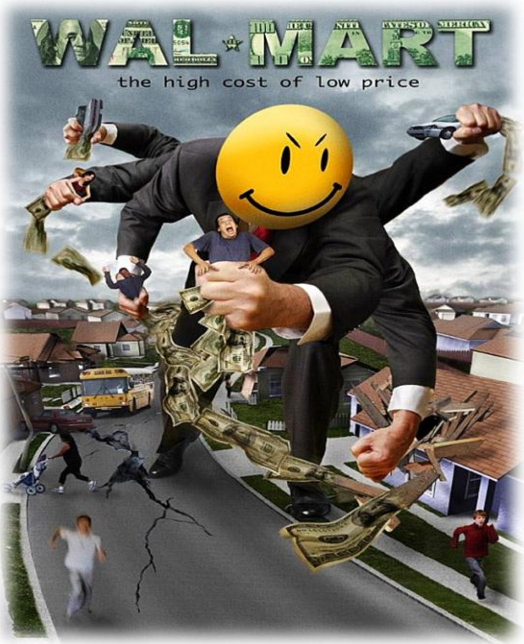

भारत को ग्राम स्वराज्य के सपने को असल में साकार करना चाहिए जिससे कि सभी लोगों के लिये दीर्घकालिक एक मानवीय सामाजिक व्यवस्था बन सके. उदहारण के तौर पर उदारीकरण नीतियों से भारत की अपनी अर्थव्यवस्था को नुक्सान ही पहुंचा है और अधिकाँश जनता, जो गरीब है, उसका जीना और अधिक दूभर हो गया है. भारत को चाहिए कि खुदरा व्यवसाय पर निर्भर लोगों को और मजदूर–किसान वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा प्रदान हो जिससे कि मजदूर या किसान आत्महत्या करने पर न विवश हों और सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकें.

खुदरा जनता के लिए हितकारी नहीं : डा.संदीप

लखनऊ (प्रभात)। खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश स्थानीय लोगों एवं देश की अर्थ व्यवस्था के लिये कितना खतरनाक हो सकता है यही दर्शाया गया है वृत्तचित्र वालमार्ट हाई कास्ट ऑफ़ लो प्राइसेश में। इस वृत्तचित्र को आज इंदिरा नगर सी ब्लाक चौराहा स्थित सर्जन प्रोफेसर डॉ रमा कान्त के केंद्र पर आशा परिवार जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय व नागरिकों का स्वस्थ के लिए छिड़े अभियान एवं सीएनएस द्वारा प्रदर्शित किया गया।

मग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता डा.संदीप पाण्डेय ने कहा कि खुदरा व्यवसाय में विदेशी पूंजी निवेश का निर्णय हमारे देश की अधिकांश जनता के [illegible]

[illegible] का ध्रुवीकरण होगा, अमीर [illegible] अधिक अमीर और गरीब [illegible] अधिक गरीब होंगे। डॉ [illegible] पाण्डेय ने कहा कि भारत को [illegible] स्वराज्य के सपने को असल [illegible] साकार करना चाहिए जिससे [illegible] सभी लोगों के लिये [illegible] एक मानवीय सामाजिक [illegible] बन सके। उदहारण के तौर [illegible] उदारीकरण नीतियों से भारत [illegible] अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान [illegible] पहुंचा है और अधिकाँश जनता [illegible] गरीब है उसका जीना और [illegible] दूभर हो गया है। भारत को [illegible] कि खुदरा व्यवसाय पर निर्भर [illegible] को और मजदूर-किसान वर्ग [illegible] लोगों के लिये सामाजिक [illegible] प्रदान हो जिससे कि मजदूर [illegible] किसान आत्महत्या करने पर [illegible]

योजना आयोग की छोटे–सीमान्त किसानों को खेतिहर मजदूर बनाने की तैयारी

तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत की 60 फीसदी से अधिक आबादी अभी भी भूमि पर निर्भर है। लेकिन बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दिशा–पत्र भूमि को गरीबों की आजीविका साधन न मानकर खदान और उद्योगीकरण के लिए कच्चा माल मानता है। दिशा–पत्र का पैराग्राफ 5.24 इस प्रकार है ''तीव्र वृद्धि केवल तभी संभव है यदि कुछ जमीन, जो इस समय कृषि कार्य के लिए इस्तेमाल हो रही है, या जो बेकार जंगल की भूमि हो, इन कार्यों के लिए उपलब्ध करायी जा सके, बहुत जरूरी इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण कार्य के लिए, नयी औद्योगिक इकाइयाँ खड़ी करने के लिए। जो सवाल उठता है वह यह है कि इन गतिविधियों के लिए जरूरी भूमि कैसे प्राप्त की जाय।''

इसके अतिरिक्त दिशा–पत्र यह भी चाहेगा कि सीमान्त किसानों से भूमि लेकर बड़े काश्तकारों को हस्तान्तरित कर दी जाय और छोटे किसानों को, खेतिहर मजदूर बना दिया जाय। यह पत्र ऐसे कानून की वकालत करता है जो छोटे किसानों को, जिनकी खेती अलाभकर है, अपनी भूमि ऐसे लोगों को लीज पर देने की इजाजत दे जो खेती में अन्य आवश्यक लागत सामान जुटा सकें। नये काश्तकार इन छोटे सीमांत किसानों को अपनी भूमि पर काम करने के लिए रख सकेंगे। आखिरी बात यह है कि राज्यों द्वारा वनाधिकार कानून का खुल्लमखुल्ला उल्लंघन पर मौन है जबकि राज्य वनों पर समुदायों के अधिकार को मान्यता नहीं देते जैसा कि वनाधिकार कानून की अपेक्षा है।

जहां तक भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम की बात है जो सार्वजनिक हो गया था जब दिशा–पत्र को अन्तिम रूप दिया जा रहा था। योजना आयोग से इसकी मुख्य धाराओं का मजबूती से समर्थन अपेक्षित था जैसे 80 फीसदी किसानों की सहमति, पंजीकृत कीमतों का चार गुना मुआवजा और भविष्य में भूमि की कीमत में वृद्धि का 20 फीसदी किसानों का शेयर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पत्र में मात्र इतना कहा गया है किसानों से जमीन अधिग्रहण करने की कीमत तय करने के

तेज आर्थिक वृद्धि के बावजूद भारत की 60 फीसदी से अधिक आबादी अभी भी भूमि पर निर्भर है। लेकिन बारहवीं पंचवर्षीय योजना का दिशा–पत्र भूमि को गरीबों की आजीविका साधन न मानकर खदान और उद्योगीकरण के लिए **कच्चा माल** मानता है।

तरीके का सावाधानी से अध्ययन होना चाहिए जिससे एक तो जिनसे भूमि ली जा रही है, उनके साथ न्याय हो और दूसरे वह अवास्त विकरूप से ऊंचा न हो (पैरा 5.30)। दिशा–पत्र में यह भी अपेक्षा की गयी है कि सार्वजनिक उद्देश्य की परिभाषा में उद्योग और निजी कम्पनियों के लिए ली जाने वाली भूमि विशेष रूप से शामिल की जाय (पैरा 5.31)। किसका हित साधन किया जा रहा है, यह जाहिर है।

छोटे सीमान्त किसानों का भूमिहीन मजदूर बनाने की योजना :

योजना आयोग में छोटे–सीमान्त किसानों के प्रति उपेक्षा भाव है और उसकी कोशिश है कि उन्हें भूमिहीन मजदूर बना दिया जाय। यह गंभीर बात है। आयोग की यह सोच न केवल गरीब विरोधी है बल्कि उत्पाद विरोधी भी है। आकार–उत्पादकता सम्बन्ध पर की गयी शोध यह बताती है कि छोटे खेत से उत्पादन बड़े खेतों के मुकाबिले अधिक होता है। कृषि अर्थशास्त्रियों ने इकोनोमिक एण्ड पोलीटीकल वीकली जून 25, 2011 के अंक में नेशनल सैम्पल सर्वे के आकड़ों के आधार पर यह बताया है कि भारतीय कृषि ने छोटी काश्त बड़ी काश्त के मुकाबिले उच्चतर उत्पादकता देती है। इसका एक कारण यह है कि छोटी काश्त पर किसान खुद मेहनत करता है, अपना खाद डालता है जबकि बड़ी काश्त पूंजी और किराये की मजदूरी पर चलती है।

बाजार और प्रौद्योगिक शक्तियां भूमि को कुछ हाथों में केन्द्रित करने के पक्ष में होती हैं। यदि सरकार इसे रोकने का कोई कार्यक्रम लागू नही करती तो वर्तमान परिस्थितियों में गैरबराबरी के चलते ग्रामीण गरीबों की गरीबी और बढ़ेगी। इस तौर तरीके पर चिन्ता प्रकट करने, छोटे किसानों को ऋण, लागत सामान और बाजार मुहैया कराने और कृषि के बाहर रोजगार पैदा करके उनकी आमदनी में बढोत्तरी करने की बजाय योजना आयोग बड़े काश्तकारों के पक्ष में काम करने और उन्हें और बड़ा बनाने की चाह रख रहा है।

महिला किसानों की समस्याओं की अनदेखी :

पुरुषों के गांवों से बड़ी संख्या में शहरों की ओर पलायन करने से खेती किसानी का दारोमदार महिलाओं पर आ पड़ा है। उत्पादक परिसम्पतियों–भूमि,

योजना आयोग में छोटे–सीमान्त किसानों के प्रति उपेक्षा भाव है और उसकी कोशिश है कि उन्हें भूमिहीन मजदूर बना दिया जाय। यह गंभीर बात है। आयोग की यह सोच न केवल गरीब विरोधी है बल्कि उत्पाद विरोधी भी है। आकार–उत्पादकता सम्बन्ध पर की गयी शोध यह बताती है कि **छोटे खेत से उत्पादन बड़े खेतों के मुकाबिले अधिक होता है।**

पशुधन, मछली, प्रौद्योगिक, ऋण, वित्त, बाजार आदि पर महिलाओं का नियंत्रण नहीं है, साथ ही सामाजिक–सांस्कृतिक परम्पराओं के कारण उनके साथ भेदभाव भी होता है, उनको वेतन पुरुष से कम मिलता है। इन समस्याओं का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है यदि महिलाओं के भूमि पर अधिकार को राजस्व रिकार्ड में मान्यता मिल जाय। हिन्दू उत्तराधिकार कानून 2005 से उन्हें यह मिला है पर राज्य सरकारें उसे लागू नही कर रहीं। योजना आयोग को इस भूल को सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

वनाधिकार कानून को लागू करने में ढिलाई :

दिशा पत्र के पैरा 11.16 में वनाधिकार कानून को तेजी से लागू करने की बात कही गयी है पर 2006 में पास हुए इस कानून को पिछले चार साल में लागू करने में क्यों ढिलाई हुई, इसका विश्लेषण इस पत्र में नहीं किया गया है। वनवासियों को वनों पर सामुदायिक अधिकार अभी तक नही मिले है। इससे उनमें भारी असंतोष है।

लेखक की अध्यक्षता में हाल में बनी एक सरकारी समिति ने इस कानून को लागू करने में बहुत सी खामियां पायी। उदाहरण के लिए जिस क्षेत्र पर आदिवासियों को बसाया गया है, वह उनकी जरूरतों से बहुत कम है।

– सुरेश चन्द्र सक्सेना
(पीएनएन)

महिलाओं की समस्याओं का कुछ हद तक निराकरण हो सकता है यदि महिलाओं के भूमि पर अधिकार को राजस्व रिकार्ड में मान्यता मिल जाय। हिन्दू उत्तराधिकार कानून 2005 से उन्हें यह मिला है पर राज्य सरकारें उसे लागू नही कर रहीं। योजना आयोग को इस भूल को सुधारने की दिशा में कदम उठाने चाहिए।

योजना आयोग से इसकी मुख्य धाराओं का मजबूती से समर्थन अपेक्षित था जैसे 80 फीसदी किसानों की सहमति, पंजीकृत कीमतों का चार गुना मुआवजा और भविष्य में भूमि की कीमत में वृद्धि का 20 फीसदी किसानों का शेयर, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस पत्र में मात्र इतना कहा गया है किसानों से जमीन अधिग्रहण करने की कीमत तय करने के तरीके का सावाधानी से अध्ययन होना चाहिए...

वर्तमान व्यवस्था का विकल्प खड़ा करने का सही समय

यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेशवाद का लम्बा दौर चला जिसमें पश्चिम यूरोप के देशों ने लातिनी अमरीका, अफ्रीका और एशिया के संसाधन–सम्पन्न देशों की भरपूर लूट की और दुनियाभर से बटोरी सम्पत्ति के बल पर उद्योग केन्द्रित, पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल खड़ा किया।

आगे चलकर इस मॉडल को अपनाने और उसे लागू कराने में यूरोप के साथ संयुक्त राज्य अमरीका और जापान शामिल हो गये। दूसरे विश्व युद्ध के बाद उपनिवेश स्वतंत्र होते गये, परन्तु शोषण का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। राज्य उपनिवेशवाद का स्थान कारपोरेट उपनिवेशवाद ने ले लिया। पुराने उपनिवेशों में औद्योगिक देशों के बड़े–बड़े कारपोरेट विकास करने के नाम पर घुसते गये।

औद्योगिक देशों द्वारा नियंत्रित अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की तिकड़ी– विश्व बैंक, मुद्राकोष, डब्लूटीओ ने पूंजीवादी मॉडल को फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। भूमण्डलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण की नीतियाँ धार्मिक विश्वास की तरह देशों पर कर्ज और व्यापार के दबाव में लादी गयीं। इस मॉडल की चमक–दमक भी आकर्षक रही है और यह मॉडल कमोवेश दुनिया में चल रहा है।

इस मॉडल का मानव और प्रकृति विरोधी चरित्र समय–समय पर उजागर होता रहा है। बीसवीं सदी में मार्क्स और गांधी ने इसे चुनौती दी। मार्क्स के सिद्धांतों पर सोवियत संघ ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का विकल्प खड़ा किया जो चीन, क्यूबा, वियतनाम जैसे और पूर्वी यूरोप के देशों में फैला।

इस मार्क्सवादी मॉडल में संसाधनों की मालकियत कारपोरेटों के हाथ में न रखकर राज्य के हाथ में रखी गयी पर उत्पादन तंत्र वही रहा जो पूंजीवादी व्यवस्था में था। बीसवीं सदी के अंत तक यह विकल्प ध्वस्त हो गया, सोवियत संघ खण्डित हो गया, चीन भी धीरे–धीरे पूंजीवाद मॉडल की तरफ झुकता गया। अब दुनिया में पूंजीवादी कारपोरेटी मॉडल ही एकमात्र मॉडल है और यह प्रचारित किया गया कि कोई अन्य विकल्प नहीं है।

यूरोप में हुई औद्योगिक क्रांति के बाद उपनिवेशवाद का लम्बा दौर चला जिसमें पश्चिम यूरोप के देशों ने लातिनी अमरीका, अफ्रीका और एशिया के संसाधन–सम्पन्न देशों की भरपूर लूट की और दुनियाभर से बटोरी सम्पत्ति के बल पर उद्योग केन्द्रित, पूंजी आधारित अर्थव्यवस्था का मॉडल खड़ा किया।

गांधी जी ने जो मॉडल सुझाया, वह पूंजीवादी और मार्क्सवादी दोनों से भिन्न है। इसमें संसाधनों की मालकियत जन समुदायों के हाथ में रहे, उत्पादन तंत्र का आधार भारी उद्योग न होकर लघु उद्योग हों, पूरे मॉडल में गांव मुख्य इकाईयां बने। गांधी के विचार से बना यह मॉडल लोगों को रोजगार देगा, सम्पत्ति संसाधनों की लूट रुकेगी और समतामूलक अहिंसक समाज की रचना हो सकेगी। भारत की आजादी के बाद गांधीजी अपने मॉडल को लागू करते, उससे पहले ही वे शहीद हो गये। गांधी का नाम लेने वाली सरकारों ने गांधी के मॉडल को अपनाया नहीं, वे पूंजीवादी और मार्क्सवादी मॉडलों के घाल–मेल में फंसी रहीं।

वर्तमान मॉडल का विकल्प खोजनें की कोशिशें होती रही हैं। इस मॉडल ने सबसे ज्यादा विनाश लातिनी अमरीका में किया है। इसका एक बड़ा कारण यह है कि इस मॉडल का सबसे बड़ा पुरोधा संयुक्त राज्य अमरीका है और लातिनी अमरीका को अपना ऑगन ;ठंबा ल्तकद्ध मानता रहा है। इस महाद्वीप में पिछले 15–16 साल से इस मॉडल के कारण देशों की मुद्राएँ धूल में मिल गयी, गरीबी, बेरोजगारी, गैर बराबरी चरम सीमा पर पहुंच गयी और देश भारी कर्ज में डूब गये। इससे लोगों में आक्रोश पैदा हुआ और कई देशों में इस मॉडल को काफी हद तक नकार दिया है और लातिनी अमरीका के मुक्ति दाता बोलीवार के विचार पर आधारित मॉडल गढ़ने में ये देश लगे हैं।

भारत में से छिटपुट कोशिशें हुई है विकल्प की खोज में। परन्तु वर्तमान मॉडल उदारवाद का जामा पहनकर रोल रॉलर की तरह–ऐसे सभी प्रयासों को रौंदता रहा है। सरकारें, कारपोरेट मिलकर वर्तमान मॉडल का महिमा मण्डन कर रहे हैं और विकल्प की तलाश को दबाते रहे हैं।

परन्तु इस समय कुछ अनुकूल माहौल बन रहा है। इस मॉडल के प्रणेता और प्रचारक यूएस और यूरोप में ही इस समय इस मॉडल की पोल खोल हो रही है। कारपोरेटी लालच ;ळतममकद्ध और बेरोजगारी से मारे हुए अमरीकी और युरोपवासी इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। नतीजन इस मॉडल का महिमा खण्डन होने लगा है। यह सही समय है जब भारत में व्यवस्था परिवर्तन में लगे जन आंदोलनों, जन संगठनों और सामाजिक सरोकार करने वाले बुद्धिजीवियों को मिलकर इस मॉडल को नकार दें और जनसमुदाय की संसाधनों पर मालकियत और उसका निर्णय लेने के अधिकार पर विकेन्द्रित उत्पादन विधि आधारित मॉडल को लागू करें।

– डॉ. बनवारी लाल शर्मा

(पीएनएन)

सोमालिया में मुद्राकोष और विश्व बैंक ने पैदा किया अकाल

सोमालिया ग्रामीण अर्थव्यवस्था का देश था धुमन्तु पशुपालकों और छोटे किसानों के बीच अदला बदली के सहारे वहां की अर्थव्यवस्था चलती थी। ये घुमन्तु ग्रामीण वहां की आधी आबादी थे। 1970 के दशक में पुनर्वास कार्यक्रमों के चलते काफी संख्या में घुमन्तु पशुपालक व्यवसायिक पशुपालकों में तब्दील हो गये। 1983 तक देश की निर्यात आमदनी का 80 प्रतिशत हिस्सा पशुधन के निर्यात से प्राप्त होता था। बार–बार आने वाले सूखों के बावजूद 1980 तक सोमालिया भोजन के मामले मे लगभग आत्म निर्भर रहा।

1980 के शुरुआती वर्षों में सोमालिया में आइ एम एफ–विश्व बैंक की घुसपैंठ से सोमालिया कृषि का संकट बदतर हो गया। आर्थिक सुधारों के कारण घुमन्तु अर्थव्यवस्था के और आसीन अर्थव्यवस्था अर्थात घुमन्तु और छोटे किसानों के बीच की अदला बदली के नाजुक संबंध छिन्न भिन्न हो गये।

सरकार पर बहुत ही कठोर खर्च कटौती कार्यक्रम थोप दिये गये और उनसे बचे हुए पैसों को सोमालिया पर पेरिस क्लब के चढ़े हुए कर्जों के भुगतान में लगाया गया। सरंचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों के चलते सोमालिया की निर्भरता आयातित खाद्यान्न पर बढ़ती चली गयी। 1970 के मध्य तक विदेशी खाद्यान्न मदद में 15 गुनी वृद्धि हुई प्रतिवर्ष 31 प्रतिशत की दर से। बढ़ते हुए व्यापारिक आयात के साथ यह जुड़ गया और इसके बाद जो सस्ते चावल और गेंहू की घरेलू बाजार में बाढ़ जैसी आयी, उसने परम्परागत फसलों को रौंदते हुए भोजन उपयोग तौर तरीका भी बदल दिया।

सोमालिया की मुद्रा शिंलीग का अवमूल्यन आईएमएफ विश्व बैंक के निर्देशों पर जून 1981 में किया गया और उसके बाद छोटे मोटे अवमूल्यन लागातार होते रहे जिसके कारण ईधन, खाद और कृषि आगतों की कीमतें बढती चली गयी। इस सभी का प्रभाव किसानों पर तुरंत हुआ, खासतौर से वर्षा आधारित कृषि पर परन्तु सिंचित खेती पर भी। शहरी लोगों की कय शक्ति आश्चर्यजनक रूप से घटी, सरकार के प्रसार कार्यक्रमों में कटौती हुई, मूलभूत संरचना धराशायी हो गयी और खाद्य बाजारों का विनियमन तथा 'खाद्य सहायता' की बाढ़ ने कृषक समुदायों को पंगु बना दिया।

सरकार पर बहुत ही कठोर **खर्च कटौती कार्यक्रम** थोप दिये गये और उनसे बचे हुए पैसों को सोमालिया पर पेरिस क्लब के चढ़े हुए कर्जों के भुगतान में लगाया गया।

इसी दौरान बहुत सी खेती योग्य भूमि पर नौकरशाहों सैनिक अधिकारियों, व्यापारियों ने सरकार के साथ मिलकर कब्जा कर लिया। कर्जा देने वालों ने खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहित करने के बजाय तथाकथित उंचे मूल्यों के फलों, सब्जियों, तिलहनों और कपास के उत्पादन को निर्यात के लिए सर्वोत्तम कृषि भूमि पर पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया।

1980 के दशक के दौरान ही पशुओं के लिए जरुरी आयातित दवाओं के दाम बढे क्योंकि मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था। घुमन्तु पशु पालकों के लिए जरुरी वेटरीनरी सेवाओं तथा पशुओं के टीकाकरण की फीस बढ़ाने के लिए विश्व बैंक ने जोर डाला जिससे पशु दवाओं का प्राइवेट बाजार फलफूल सके।

पशुधन मत्रांलय की भूमिका सीमित कर दी गयी, मत्रांलय की वेटरीनरी प्रयोगशाला सेवाओं का खर्च कीमत के आधार पर चलाया गया। विश्व बैंक मुताबिक ''पशुधन विकास के लिए वेटरीनरी सेवाऐं जरूरी है और वे केवल निजी क्षेत्र द्वारा ही उपलब्ध करायी जा सकती है।'' अब चूंकि इक्का दुक्का वेटरीनरी डाक्टर ही दूरदराज के इलाकों में पशुपालक अपने पशुओं के स्वास्थ्य के लिये 'पैरा–वेट', सेवाओं, जो दवा बिक्री के पैसे से चलायी जा रही थी, पर निर्भर हो गये।

पशु स्वास्थ्य के निजीकरण का मामला, सूखे के समय पशु आहार की अनुपलब्धता से, पानी के व्यवसायीकरण से, और पानी और जमीन के सरंक्षण की अनुपस्थिति से जुड़ गया। परिणाम जाने

शहरी लोगों की क्रय शक्ति आश्चर्यजनक रूप से घटी, सरकार के प्रसार कार्यक्रमों में कटौती हुई, मूलभूत संरचना धराशायी हो गयी और खाद्य बाजारों का विनियमन तथा 'खाद्य सहायता' की बाढ़ ने कृषक समुदायों को पंगु बना दिया।

पहचाने थे, पशुओं के झुण्डों का सामुहिक सफाया हो गया और उनके साथ ही घुमन्तु आबादी का जो कि देश की 50 प्रतिशत थी। इसे पूरे कार्यक्रम का 'छुपा उद्देश्य' परम्परागत अर्थव्यवस्था की रीढ़–घुमन्तु पशुपालकों का सफाया था ही। विश्व बैंक के मुताबिक घुमन्तु पशुपालकों के समूहों के आकार में समायोजन लाभकारी ही रहा क्योंकि सब सहारा अफ्रीका में ये जन जातियां पर्यावरण विनाश के लिए भी दोषी मानी जाती है।

वेटरीनरी सेवाओं के धराशायी होने का भी असली फायदा अप्रत्यक्ष रूप से धनी देशों को ही हुआ। 1984 में सऊदी अरब और खाड़ी के देशों को होने वाला सोमालियाई पशुओं का निर्यात गिर गया क्योकिं सऊदी अरब ने अपने गोमांस आयात को आस्ट्रेलिया और यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं की तरफ मोड़ दिया। सऊदी अरब ने सोमालियाई मांस के आयात पर लगे प्रतिबन्ध को तब भी

नहीं हटाया जब वहां से पशुओं की रिडरपेस्ट महामारी खत्म हो गयी।

ब्रेटन वुड्स संस्थाओं की देखरेख में सरकारी खर्चों का पुनर्निधारण भी खाद्य कृषि व्यवस्था को नष्ट करने का एक बड़ा कारण बना। कृषि का बुनियादी ढांचा टूट गया और कृषि पर होने वाला खर्च 1970 के दशक के मुकाबले 85 प्रतिशत घट गया। आइ एम एफ ने सोमालियाई सरकार को घरेलू संसाधन जुटाने से भी रोक दिया। बजट घाटे के पूरा करने के लिए कठोर लक्ष्य तय कर दिये गये।

और, दानदताओं ने भी जो मदद दी वह पूंजी और तकनीक के हस्तांतरण के रूप में नही बल्कि खाद्यान्न मदद के रूप में दी। और मदद में आया यही खाद्यान्न सरकार द्वारा स्थानीय बाजारों में बेचा गया और इस ब्रिकी से प्राप्त राशि को ही विकास परियोजनाओं की घरेलू लागत को पूरा करने में उपयोग किया गया। 1980 के दशक की शुरुआत में ही खाद्यान्न मदद में हासिल पैसा राज्य के राजस्व का प्रमुख स्रोत बन गया और इस तरह राज्य के बजट पर पूरा नियंत्रण दानदाताओं के हाथ में पहुंच गया।

आर्थिक सुधारों के साथ ही स्वास्थ्य और शिक्षा कार्यक्रम छिन्न भिन्न हो गये। 1989 तक स्वास्थ्य कार्यक्रमों पर होने वाला खर्च 1975 के स्तर से 78 प्रतिशत गिर गया। विश्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक 1989 में प्राइमरी स्कूल के एक विद्यार्थी पर प्रतिवर्ष 4 डालर खर्च हो रहे थे जबकि 1982 में यही खर्च 82 डालर था। 1981 से 1989 के बीच स्कूल में दाखिला लेने वाले छात्रों की संख्या में 41 प्रतिशत गिरावट आयी जबकि इसी दौरान स्कूल जाने योग्य बच्चों की जनसंख्या में बढ़ोत्तरी हुई। कक्षाओं से किताबे और पाठन सामग्री गायब हो गयी, स्कूल भवनों में दुर्दशा छा गयी। करीब एक चौथाई प्राइमरी स्कूलों का स्तर गिरकर निम्नतम स्तर पर पहुंच गया।

आइ एम एफ विश्व बैंक के कार्यक्रमों ने सोमाली अर्थ व्यवस्था को एक दुश्चक्र में फंसा दिया। पशुओं के खात्मे से घुमन्तु पशुपालक भुखमरी के कगार पर पहुंच गये, और बदले में अनाज उत्पादक भी प्रभावित हुए जो इन पशुपालकों को पशु आहार के रूप में अनाज बेचते थे। इस तरह से घुमन्तु अर्थव्यवस्था का पूरा सामाजिक ताना बाना छिन्न–भिन्न हो गया। घटते पशु निर्यात के कारण टूटी विदेशी मुद्रा की कमाई से भुगतान सन्तुलन और सार्वजनिक वित्त व्यवस्था गड़बड़ा गयी और उससे सरकार के आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम बिखर गये।

सस्ता अमरीकी अनाज घरेलू बाजारों में भर गया और उधर कृषि आगतों की कीमतों में बढ़ोत्तरी हुई। दोनों बातों ने मिलकर छोटे किसानों की खेती तबाह कर दी और वे कृषि से विस्थापित हो गये। शहरी आबादी की बढती गरीबी के कारण खाद्य उपभोग कम हुआ। सिंचित क्षेत्रों को मिलने वाली राज्य सहायत बन्द हो गयी और सरकारी फार्मो में उत्पादन घट गया। बाद में ये सरकारी फार्म विश्व बैंक की सलाह पर निजी उद्योगों को बेच दिये गये।

विश्व बैंक के आकलन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों में मिलने वाले वेतन 1970 के मुकाबले 1989 में 90 प्रतिशत कम हो कर 3 डालर प्रतिमाह के औसत पर आ गये इससे नागरिक प्रशासन छिन्न–भिन्न हो गया। विश्व बैंक ने नागरिक सेवाओं के पुनर्गठन का प्रस्ताव रखा लेकिन इसके तहत 40 प्रतिशत सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों की छटनी और कर्मचारियों के भत्तों में कटौती की जानी थी। इस कार्यक्रम के तहत नागरिक सेवाओं में कर्मचारी घट कर 1995 में केवल 25,000 कर्मचारी रह जाने थे (60 लाख की आबादी वाले देश में)। नागरिक सेवाओं में छटनी से जुड़े खर्चों की भरपाई के लिए दानदाता पैसा देने के लिए तैयार थे।

आसन्न संकट के मददेनजर, अंर्तराष्ट्रीय कर्ज दाता समुदाय ने देश की आर्थिक और सामाजिक मूल संरचना को पुनर्गठित करने, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ाने, नागरिक सेवाओं को पुनर्गठित करने में कोई रुचि नही दिखायी। जनवरी 1991 में जनरल सियाद बेचारे की सरकार के धराशायी होने के एक वर्ष पहले कर्जदाताओं ने वृहत आर्थिक समायोजन कार्यक्रमों के तहत सार्वजनिक खर्चों में कटौती, केंद्रीय बैंक के पुनर्गठन, क्रेडिट के उदारीकरण और सार्वजनिक उद्यमों के विनिवेश और बिक्री के लिए कहा।

1989 में कर्ज भुगतान की जिम्मेदारी कुल निर्यात आय का 194.6 प्रतिशत हो गयी। सोमालिया की बढती कर्ज जिम्मेदारियों को देखते हुए आइ एम एफ ने नये कर्ज निरस्त कर दिये, जबकि

विश्व बैंक के आकलन के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्रों में मिलने वाले वेतन 1970 के मुकाबले 1989 में 90 प्रतिशत कम हो कर 3 डालर प्रतिमाह के औसत पर आ गये इससे नागरिक प्रशासन छिन्न–भिन्न हो गया।

जून 1989 में ही विश्व बैंक संरचनात्मक समायोजन के लिये 7 करोड़ डालर के कर्ज स्वीकृत कर चुका था जिन्हें सोमालिया की खराब वृहत आर्थिक निष्पादन क्षमता को देखते हुए कुछ महीने बाद ही रोक दिया गया। नये कर्जों की स्वीकृति से पहले कर्ज बकाये का भुगतान होना जरूरी कर दिया गया। सोमालिया कर्ज के भुगतान और संरचनात्मक समायोजन के जाल में फंस गया। बाकी तो इतिहास है।

सोमालिया का अनुभव बताता है कि कैसे एक देश वृहत आर्थिक नीतियों द्वारा तहस नहस हो सकता है। विकासशील देशों में तमाम सोमालिया है और सोमालिया में लागू किया गया आर्थिक सुधार पैकेज के समान ही पैकेज 80 विकासशील देशों में लागू किये गये। लेकिन इसका और भी एक महत्वपूर्ण आयाम है। सोमालिया घुमन्तु पशुपालकों की अर्थव्यवस्था रही है और पूरे अफ्रीका में धुमन्तु पशुपालकों की अर्थव्यवस्थाओं को आइ एम एफ विश्व बैंक द्वारा वैसे ही क्षति पहुंचायी जा रही है जैसे कि सोमालिया में।

– प्रो0 माइकल चाऊसोदोवस्की

(पीएनएन)

Exclusive for
Pre Engineering Entrance Test
IIT, AIEEE, UPTU, AMU etc.

S.Ahmad

PMT COLLEGE

Best Institute in UP for Medical/Engg. Entrance Exam

- **Head Office:** 31/56 M.G.Marg, Above BATA & KAYSONS Showrooms opp. Hotel Capoor, Near Sahu Cinema, Hazratganj, Lko.
  Ph: 0522-2616637, 0522-4067821, Fax: 0522-4072185, 9415005426
- **Branch Gorakhpur:** Pratap Market, 1st floor, Cinema Road, Golghar.
  Ph: 933640443, 8953256393

Branches: HARDOI RAIGARH BILASPUR BHILAI

Designed by www.Jay-inspire.com

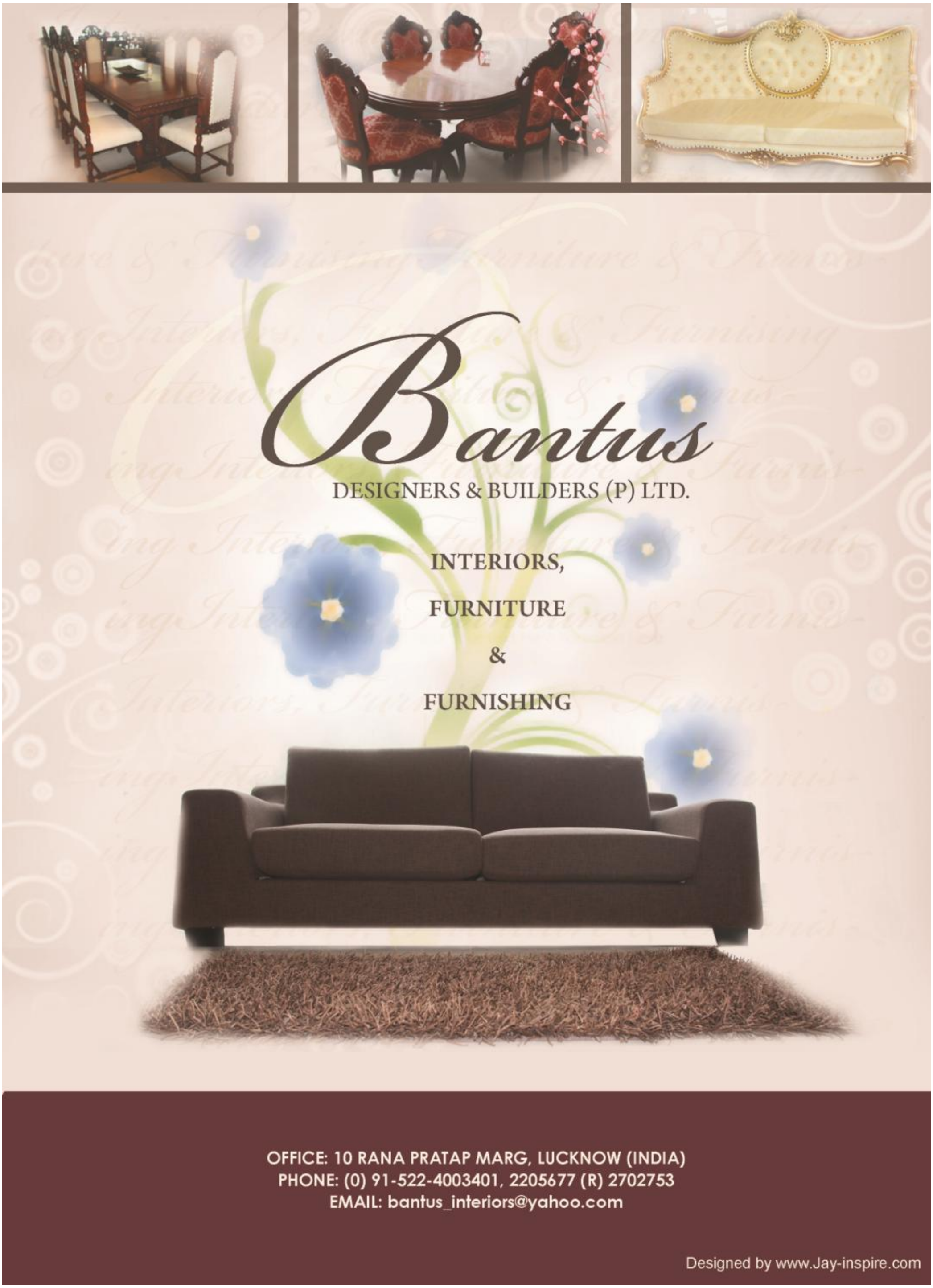
Bantus
DESIGNERS & BUILDERS (P) LTD.
INTERIORS,
FURNITURE
&
FURNISHING
OFFICE: 10 RANA PRATAP MARG, LUCKNOW (INDIA)
PHONE: (0) 91-522-4003401, 2205677 (R) 2702753
EMAIL: bantus_interiors@yahoo.com
Designed by www.Jay-inspire.com